



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यपालन द्वारा प्रकाशित

सिमला, शनिवार, १७ दिसम्बर, १९९४/२६ ग्रन्हायण, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अभिसूचना

सिमला-१७१००२, १७ दिसम्बर, १९९४

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (४)-१/९४.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-के० और २४३-जेड० ए० के खण्ड (२) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९९४ (१९९४ का ४) की धारा १६० और १८६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा सतें) नियम, १९९४, जिन्हें पहले ही सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के नाम से निम्न नियम

मनाने के सहित आदेश प्रदान करते हैं :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्त) नियम, 1994 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ग) “राज्य चुनाव आयुक्त” से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-कं० और 243-जेड ए० के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अधीन नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त अभिप्रेत है;

(2) अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वेतन.—राज्य चुनाव आयुक्त को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन संयोजन किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण की तारीख से पूर्व, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अधीन की गई सेवा या के विषय में (निष्काशा या क्षति पैदा करने से अन्यथा) पेंशन प्राप्त कर रहा था या पेंशन में प्राप्त है, और उसके पेंशन लेने का निर्धारण किया था, तो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा के लिए उसके वेतन से निम्नलिखित घटाई जाएगी :—

(क) उनकी पेंशन की राशि; और

(ग) यदि उसके पद ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के आधार पर उसे वेतन पेंशन के धारक में पेंशन के भाग की राशि, जिस पर मासिकीकरण मूल्य दिया गया है :

परन्तु यह और कि जब किसी व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में उस समय नियुक्त किया जाता है जबकि वह सरकारी सेवा में हो तो वह अधिवर्तिता की आयु पूरा करने पर सेवा निवृत्त होगा और उसके पश्चात् उसका वेतन पूर्ववर्ती उपरोक्तों के अनुसार कम किया जाएगा।

4. पद, शक्ति.—राज्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से, शक्ति की शर्तों के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु वह किसी भी समय राज्यपाल की दख्खीयत करके अपने हाथ से विदा कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

5. अधिनियम.—(1) कोई व्यक्ति जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद-ग्रहण करने की तारीख से पूर्व सरकारी सेवा में था जो उसकी पदशक्ति के दौरान उस सेवा के अंतर्गत वह ऐसी तारीख से पूर्व सम्मानित है जो तत्काल प्रवृत्त आयु नियमों के अन्तर्गत आदेश प्रदान किया जाएगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं और वह ऐसी तारीख की अगले साल में जमा अवकाश के अधिपत्र का हकदार होगा।

(2) कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो राज्य चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, को ऐसे नियमों के अधीन असाधारण प्रवेश दिया जाएगा जो तत्काल हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को लागू हों।

(8) राज्य चुनाव आयोग को अवकाश प्रदान करने, उसे अस्वीकार करने और प्रतिस्पर्धा करने या काम करने की क्षमता राज्यपाल में निहित होगी।

6. अवकाश के पक्ष में मतदान भुगतान:—राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को स्वीकार्य अवकाश के पक्ष में मतदान भुगतान के असाधारण प्रवेश के पक्ष में मतदान भुगतान का हकदार होगा।

वर्षानु अथवा कोई ऐसा नियम व्यक्ति राज्य चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त किया जाता है और उम्मेदवार अपनी अवकाश के पक्ष में, अवकाश के पक्ष में मतदान भुगतान प्राप्त किया है, तो यह अवकाश पर अवकाश के पक्ष में प्राप्त किए गए मतदान और 240 दिनों के अवकाश के अंतर का बचि कोई हो, हकदार होगा।

7. सेवा की अवधि:—इन नियमों में अवकाश अवधि के विषय, राज्य चुनाव आयोग, अवकाश यात्रा विधायक जो हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को अनुमति है, आकाश मूल्य में नगरीय आवास या इनके स्थान पर 2,500 रुपये प्रतिमास, एक कार्यालय में और दूसरा आवास स्थान पर दूरस्थ बुनियादी, प्रतिमास 400 रुपये की दर से सरकार जमा और नियुक्त बाह्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा तथा अब यह सरकारी योरे पर हो तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को मिलने वाले वैनिक भरतों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को समान विविध सुविधाओं भी प्राप्त करने के हकदार होंगे।

8. पुनः नियुक्ति:—राज्य चुनाव आयोग, इन नियमों में नियम 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति का पक्ष लगी होगा।

आदेश द्वारा,

श्री 0 श्री 0 यादव,

हिम उपायन, आयुक्त एन सचिव।

[Authoritative English text of Government Notification No. PCH-HA (4)-1/94, dated 17th December, 1994, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th December, 1994

No. PCH-HA (4)-1/94. In exercise of the powers conferred by section 160 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) read with clause (2) of Article 243-K and 243 ZA of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules entitled as the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994, the same having been previously published in the Official Gazette : —

RULES

1. Short title.—(1) These rules may be called the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) “Governor” means the Governor of the State of Himachal Pradesh; and

(c) “State Election Commissioner” means the State Election Commissioner appointed under section 160 of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1994 read with articles 243-K and 243-ZA of the Constitution of India.

(2) All other words and expressions used in these rules, but not defined herein, shall have the same meanings as are assigned to them in the Act.

3. *Salary.*—There shall be paid to the State Election Commissioner a salary which is equal to the salary of a Judge of the High Court:

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in receipt of or, being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union, his salary in respect of services as the State Election Commissioner shall be reduced:—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous services the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that when a person is appointed as State Election Commissioner while in service of the Government shall retire from service on attaining the age of superannuation and thereafter his salary shall be reduced in accordance with the foregoing proviso.

4. *Term of Office.*—The State Election Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes his office:

Provided that he may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

5. *Leave.*—(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in service of Government, may be granted during his tenure of office but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before such date and he shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date.

(2) Any other person who is appointed as the State Election Commissioner may be granted leave in accordance with such rules as are for the time being applicable to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government,

(3) The power to grant or refuse leave to the State Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the Governor.

6. *Leave encashment.*—The State Election Commissioner shall be entitled for leave

encashment as admissible to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government :

Provided that when a retired person is appointed as the State Election Commissioner and has received leave encashment after his superannuation he shall be entitled for the difference, if any, between the leave encashment he received at the superannuation and 240 days.

7. *Other conditions of services.*—Save as otherwise provided in these rules, the State Election Commissioner shall also be entitled for Leave Travel Concession as per entitlement of a grade-I Officer of the State Government, rent free semi-furnished accommodation or Rs. 2,500/- per month in lieu thereof, telephone facility one in the office and another at residence, sumptuary allowance Rs. @ 400/- per month and free conveyance facilities and while on official tour entitled to get daily allowance as is admissible to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government.

8. *Re-appointment.*—The State Election Commissioner shall not be eligible for re-appointment on expiry of the term specified in rule 4 of these rules.

By order,

O. P. YADAV,
Agriculture Production Commissioner-cum-Secretary.